

[श्री आकार लाल बरवा]

संमदीय दल ने मिफार्गिज की थी कि निवाइं में टॉकर और देवली हांते हुए बदी तक और टोटा रायांगह में टॉकर और देवली हांते हुए बदी तक रेलवे लाइन बिछाई जाये। मैं पूछना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय राजस्थान के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या उन्होंने राजस्थान के अनाजप्रधान क्षेत्रों में अनाज पहुँचाने के बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं ?

जहाँ तक रेलवे का सम्बन्ध है, राजस्थान का एरिया समुद्र में टापू की तरह लगता है। सर्वाइं साधोपुर तक बड़ी लाइन है और उसके आगे छोटी लाइन है। जयपुर जाने वाला माल सर्वाइं साधोपुर में कट जाता है और बैंगन न मिलने के कारण महीना बहा पड़ा रहता है। इसी तरह रतलाम तक बड़ी लाइन है और रतलाम में नमीरावाद बगैरह तक छोटी लाइन है और इस कारण माल रतलाम में पड़ा रहता है। जो माल बम्बई से आता है, वह बड़ी लाइन पर माग्वाड जकेशन पर रुक जाता है। क्या मन्त्री महोदय राजस्थान को एक टापू की तरह रखना चाहते हैं या वहाँ पर रेलवे लाइनें बिछा कर उसका विकास करना चाहते हैं ? अगर रेलवे चाहे, तो वह पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र को भी ऊपर उठा सकती है।

बैंगनों का यह हाल है कि बेचारे जानवर वालों को बैंगन नहीं मिलते हैं, जबकि पत्थर वालों को मिल जाते हैं। कोटा में अनाज वाले भी बैंगनों के लिए तरसते रहते हैं।

रेलवे ने पत्थर भरने वाली को पाच सौ या एक हजार रुपये साल के हिस्साब में प्लाट दिये हैं। जिन पत्थर वाली के पास पहले से प्लाट मौजूद है, उन्हीं को और प्लाट दे दिये गये हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है ? जो आदमी महीने में साठ बैंगन भरता है, उसके पास एक भी प्लाट नहीं है और केवल दो-चार बैंगन भरने वाली को दो प्लाट और दे दिये गये हैं। गहा जाता है कि वह जायट कम्पनी

है। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि वे लोग अन्ध-अन्ध टैक्स देते हैं।

यह डी०एम० और डी०सी०एम० साहब न जाने क्या गो नमान करते रहते हैं। 18 प्लाट टोटा देवी स्टेशन पर थे। उनको वहाँ से खत्म कर दिया गया और उनकी जगह पर कोटा में नये प्लाट बना कर बाट दिये गये। ये प्लाट उन्हीं को दिये गये जिनके पास आन्गरेडी थे। वही साल या एक हजार रुपये देते हैं। मंग मुझाव है कि प्राय एक हजार रुपये महीने पर आकेशन कीजिये। जिसको जरूरत होगी वह लेगा जिसको जरूरत नहीं होगी, नहीं लेगा। रेलवे को इनकम होगी। लेकिन प्राय यह नहीं करना चाहते। यह सब डी०एम० और डी०सी०एम० की मिली भगत है। आप सोशलिज्म की बात करते हैं, गरीबों को ऊपर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन यह सब देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि सोशलिज्म आप ला नहीं सकते।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो मुझाव मैंने दिये हैं उनको यदि आप स्वीकार करोगे और उसके अनुसार कार्य करोगे तो रेलवे में बहुत कुछ सुधार आप कर सकते हैं।

17.01 hrs.

DISCUSSION ON GURU GOBIND SINGH MEDICAL COLLEGE AT FARIDABAD

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up the discussion on the statement made by the Minister of Works and Housing and Health and Family Planning in the House on the 30th November, 1972 regarding the Guru Gobind Singh Medical College at Faridabad.

Before we begin the discussion, I would like to dispose of a matter that is connected with this discussion. Shri

Jyotirmoy Bosu may kindly listen to me till the end, without interruption, and I think you will be satisfied after hearing me through.

Shri Jyotirmoy Bosu has sent a letter to the Hon. Speaker today, which was received at 12 32 p.m., in which he has mentioned certain names that he would like to refer to in his speech. A similar situation had occurred a few days ago in connection with the debate on the rag scandal. It was ruled by the Speaker at that time that it was not enough just to send the names but it was also necessary that the matter should be mentioned, so that the Minister would have an opportunity of making inquiries into the matter and to make the discussion meaningful.

In this case, only the names were sent, and the copy of that letter was forwarded to the Minister for inquiry. But, here there is a little difference. It is not a new question. The hon. Minister in his statement on the 30th November, 1972 had made certain remarks which go to confirm that there are a number of irregularities in the establishment and the administration of this college, and, therefore, it is not as if an inquiry has not been made into this matter.

All that Shri Jyotirmoy Bosu said on the last occasion had gone on the record, and they remain on the record. So, I do not see how I can prevent the mere mention of these names which are connected with alleged irregularities which *prima facie* had been confirmed by the Minister in his statement on the last occasion. I do not see that I can prevent him from mentioning these names...

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): On a point of submission....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, he should be satisfied....

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am very much satisfied; I am grateful to

you for a change. Of course, I have very clearly mentioned the names, and I have said:

"In the context of mismanagement of Guru Gobind Singh Medical College, Fardabad, and due to their misdeeds, more than 200 boys have become ...".

So, I have given the points also. I am more than happy that you have given me permission.

डा० रक्षनी नारायण पांडेय (मदमौर) :

उपाध्यक्ष महोदय गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कॉलेज के बारे में सदन में पहले भी चर्चा हुई है। सदन में चर्चा के समय उसी वारे में कुछ नया भी सामन आये है कि किस प्रकार में उद्योग गुरु गोविन्द सिंह का नाम ले कर गुरु गोविन्द सिंह विद्या मेवक सोसायटी ने मेडिकल कॉलेज आर उसमें प्रवेश देने के नाम पर मेडिकल कॉलेज का एक बन्ध चित्र उपस्थित कर काफी रुखा एकत्र किया।

जहां तक मेरी जानकारी है प्रति छात्र 10 हजार रुपया यदि कंपिटेशन फीस के नाम पर और 10 हजार रुपये दूसरे नाम पर लिया गया और 210 के लगभग छात्रों की सख्या है तो लगभग 40 लाख रुपये इस सोसायटी ने एकत्र किये है। यह एकत्र करने की बाद में भी जो कॉलेज की दशा है वह किसी में छिपी नहीं है। मैंने स्वयं कॉलेज को देखा है और यह कहा जा सकता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए जो सामान्य से सामान्य अथवा न्यूनतम आवश्यकताएं हो सकती हैं उनकी पूर्ति भी यह कॉलेज नहीं करता। मंत्री महोदय ने 30 नवम्बर को जो बक्तव्य दिया उसमें कुछ आशय मिलता है कि हरयाना गवर्नमेंट भी कुछ इसके अन्दर लिप्त है। उसका भी इस मारी गड़बड़ी में एक प्रकार में हाथ रहा है। हरयाना गवर्नमेंट ने एक प्रकार से इस कॉलेज की स्वीकृति दी है और उसमें एक बात इसके बारे में कही है कि कॉलेज के बारे में मेडिकल

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

कौमिल से स्वीकृति प्राप्त करना चाहिये और विधिवत पंजाब यूनिवर्सिटी से स्वीकृति प्राप्त करना चाहिये, लेकिन कालेज नहीं खोला जाय ऐसा नहीं कहा गया है। अपितु, उन्होंने कहा है कि कालेज खोला जा सकता है। इस प्रकार का कालेज करनाल में खोले जाने का प्रस्ताव था और जब इस सोसायटी ने करनाल में स्थान बदल कर दूसरे स्थान पर ले जाने की बात कही तो भी हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई बात उसके बारे में नहीं की। मंत्री महोदय ने 30 नवम्बर को जो वक्तव्य यहाँ दिया उसमें लिखा है

"It appears that the Guru Govind Singh Vidya Sevak Society had sought the permission of the State Government of Haryana sometime in 1971 for setting up a medical college, at Karnal".

यह मंत्री महोदय का वक्तव्य है और वह यह भी स्वीकार करने है कि इसके अन्दर

"the situation that has occurred at Faridabad where a sub-standard medical college is alleged to have been opened last year by a private management ."

वह इन बात को भी स्वीकार कर चके है कि उसका स्टैण्डर्ड ठीक नहीं है। वह सब-स्टैण्डर्ड का है। लेकिन वह सब-स्टैण्डर्ड में भी गिरे हुये स्टैण्डर्ड का है। लाइब्रेरी को देखा जाय तो 40 पुस्तकें भी वहाँ नहीं है। किसी भी मेडिकल कालेज के अन्दर 40 पुस्तकें ही और मेडिकल कालेज जर्नल के नाम पर पूछा जाये कि कितनी पत्रिकायें आती हैं तो एक भी नाम नहीं बताया जा सकता है। एक भी पत्रिका वहाँ मिली नहीं। थोड़ा और आगे चल कर दूसरी सुविधाओं की ओर देखें तो एक भी सुविधा वहाँ नहीं माने में नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा हरियाणा गवर्नमेंट ने किस प्रकार से अपने एक दूसरे आदेश के द्वारा वहाँ पर डेड बाडीज को भी ले जाने की इजाजत दी कि डेड बाडीज वहाँ

दी जा सकती है जब कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्राइवेट मेडिकल कालेज न खोले जायें। इस कालेज के बारे में माननीय दंडवते जी के पत्र का जो उत्तर मंत्री जी ने दिया वह मेरे पास है। उसमें माफ लिखा है

"It is true that the private medical college at Faridabad referred to by you is not yet recognised by the Punjab Government or the Medical Council of India. However, no permission was required or was accorded by the Government of India since establishment of under-graduate medical colleges is a State subject".

स्टेट सबजेक्ट की बात अवश्य कही है लेकिन आपने ऊपर कहा है—स्टेट गवर्नमेंट को किस प्रकार में कालेज न खोला जाय। मैं उद्धृत करना चाहता हूँ

"The policy of the Government of India is to discourage the setting up of a medical colleges in the private sector"

यह माफ वान कही गई है स्टेट गवर्नमेंट में। आपका यह आदेश है या इसको आदेश कहना ठीक नहीं है तो आपके इमर्जेंसी का हरियाणा सरकार ने उल्लंघन किया है और उसके बाद उसने इस बात को स्वीकृति दी है यह जानते हुए कि टप प्रकार का मेडिकल कालेज खोलना ठीक नहीं है और यह भी जानते हुये कि गुरु गान्धिमिंह विद्या सेवक सोसायटी की फाइनैश्ल कडिशन अच्छी नहीं है और मैनेजमेंट ठीक कदम नहीं उठा सकता। फिर भी स्वीकृति दी यह आश्चर्य की बात है। इसी सोसायटी ने पटना में भी एक कालेज खोलने की बात कही है। वहाँ कैंपेडेशन भी भी ली गई। वहाँ पर विद्यार्थियों के जीवन को खतरों में डाला गया, उनका सारा भविष्य अधकारमय है, वहाँ भी हड़ताल चल रही है, लडके मारे मारे फिर रहे हैं, न राज्य सरकार अपना दायित्व निभा रही है और न केन्द्रीय सरकार, न मैनेजमेंट के डिप्लोमा प्रकृति प्रकार का पग उठाया कर

रहा है। मंत्री जी ने यह अवश्य अपने वक्तव्य में कहा है।

जो वक्तव्य वहाँ पर दिया गया है, उसमें लिखा है :

"I have spoken to the Chief Minister again a few days ago. He told me that he had entrusted the matter to the vigilance authorities for a detailed enquiry."

मैं कहना हूँ कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर दे तो बोलेंगे कि इनकी इन्क्वायरी हुई है या नहीं हुई है, इस मामले में कौन कौन लोग इन्क्वायर्ड हैं, इसके मंचालक कौन कौन हैं, क्या एक ही परिवार के सदस्य ना नहीं है जो मिल कर सारे का सारा घोटाला कर रहे हैं जो लाखों रुपया बनाकर इसके मैनेजमेंट को ठीक व्यवस्थान कर के विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं :

मैं आपका ध्यान हरियाणा के मुख्य मंत्री जी के संदेश को तर्क से दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने उस कालेज के आर्गनंग के समय दिया था—

"I send my good wishes on the occasion of the inauguration of the Guru Gobind Singh College and Hospital at Patna. I am sure that with the setting up of the medical college, the problem of the shortage of doctors which the country is facing at present will be solved to some extent. Such a project is a fitting memorial to Guru Gobind Singh who was much concerned with the uplift of the downtrodden and the common man."

इस तब से उन्होंने इस कालेज के लिये अपना आर्पण दिया था। मैं समझता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट भी इसमें एक पार्टी है जिसने जानते-बुझते ऐसे कालेज के खुलने के सबब आपसि नहीं की, बल्कि जो सुविधायें एक मेडिकल कालेज को मिलनी चाहिये

व सुविधायें भी दीं—जसे शासकीय हॉस्पिटल, मे जाकर जितनी प्रविटकल स्टडी करना चाहें वने प्रविटकल वने।

उपाध्यक्ष महोदय, इस गुरु गोबिन्द सिंह विद्या मेवक सोसायटी ने भी अपना एक लम्बा चौड़ा विस्तृत विवरण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने 44 लाख रुपया इकट्ठा नहीं किया है बल्कि 26 लाख रुपया इकट्ठा किया है। जिस प्रकार के आकड़े उन्होंने दिये हैं पता नहीं ये कहा तक ठीक है, लेकिन मैंने उस कालेज का देखा है। उनका एक प्रारम्भिक भी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कालिज का एक बहुत अच्छे विनिडिंग हांगो, बड़ा अच्छा बानावण होगा, लेकिन उसे देखने के बाद मैं समझता हूँ कि वहाँ ऐसी चीज नष्ट है। एक गेन्टल विनिडिंग है, जिसमें लकड़ी के हाथे रखे वरके पार्टीशन करके, बड़े पिजगो जैसा बना दिया है। वहाँ पर 210 स्टुडेंट्स हैं लेकिन उनके लिये किसी उन्नत प्रकार की लेबोरेटरी की कोई व्यवस्था नहीं है, डिमेक्शन में कितने लडके खड़े होंगे, डेड-वाडीज पर एक साथ कितने लोग डिमेक्शन वरगे कितनी डेड-वाडीज को वहाँ रखा जा सकता है—इन सब चीजों की भी वहाँ सुविधा नहीं है।

कालिज का कैंटान को भी मैंने देखा है—मडको पर जो गन्दी में गन्दी कैंटान हों, उसमें भी बदतर उस कैंटान की हालत थी। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और जिन्होंने इतना बड़ा स्कैण्डल किया, लडको के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्य-ताही नहीं की। सरकार कोई आदेश निकाल कर उस कालेज की अव्यवस्था रोक सकती थी—लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ एक बार ऐसा कहा कि इस प्रकार के कालिज में अगर छात्र प्रवेश लेंगे तो हमारा कोई उत्सदायित्व नहीं होगा—लेकिन किसी भी तरह से उनको बांधा नहीं।

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में शीघ्रता से कार्यवाही करें। जो लोग इसमें इन्वाल्ड हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। जो पता उन्होंने कपिटेशन फ्री की शकल में बसुल किया है, उसको अपने कब्जे में लें। विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में जाये, इसके लिये उन्हें किसी दूसरे मेडिकल कालेज में दाखला दिलवाने का प्रयत्न करें

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी यही हालत है।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस कालिज को अपने हाथ में लेंगे जिससे कि उन विद्यार्थियों का भविष्य सुधर सके, ताकि उनमें से जो सेवा की इच्छा रखते हैं, जो पैसे खर्च करते वहाँ आये हैं, उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिल सके। मैं यहाँ पर यह भी निवेदन कर दूँ कि इस सोसायटी ने यहीं पर नहीं, पटना में भी इसी तरह का घुटाला किया है। इस सोसायटी ने एक बहुत बड़ा पर्चा निकाला है जिसमें इसने कहा है कि हमारे पास बड़ा स्कूल स्टाफ है लेकिन वहाँ रजिस्ट्रार भी नहीं है। उनके इस वक्तव्य में यह भी कहा है कि माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है --

"The Minister has subsequently stated that the Haryana Government were not a party to the plan to start a college. That is not correct, as has been mentioned in para 6."

यहाँ पर उन्होंने आपके बारे में भी कह दिया है कि आपने जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है, मुझे दुःख है कि उसके बाद भी आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है।

इन शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो हुआ है, वह एक फ़ाउंड है, धोखा है। सरकार इस मेडिकल कालिज को अपने हाथ में ले और जो पैसा कालिज ने इकट्ठा किया है, उसको सरकार अपने कब्जे में ले तथा विद्यार्थियों का भविष्य सुधारने में मदद करे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन नहीं दिया है--आप इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें तो हालत सुधर सकती है। इस मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें जिससे कोई दूसरा इस प्रकार का व्यवहार या ठगी न कर सके।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दरखवास्त करना चाहता हूँ। श्री ज्योतिर्मय बसु जी ने यह कहा है कि वे कई नाम इस मामले में मेन्शन करना चाहते हैं और उनपर कुछ रोशनी डालना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बाद में बोलने का मौका दें--क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी है कि यह कालिज कैसे बना है, इसमें क्या घपला है। उनके भाषण के बाद मुझे उनकी बातों का जवाब देने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि श्री ज्योतिर्मय बसु पहले बोल लें, उसके बाद मैं बोलूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is a most unusual request. But I do not want to be rigid. If the hon. Members feel that it is all right to accede to his request I have no objection.

SHRI R. V. BADE (Khargone) My name is No. 2 in the list.

MR. DEPUTY SPEAKER: We do not go by No. 2 or No. 3. After the motion has been moved, we go by the party. This is a most unusual request when an hon. Member says: Give me a chance later on. It is not usual; it is not normal. If the hon. Members do not have any objection, I shall accede to his request. Shri Jyotirmoy Bosu.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: As an opposition Member I politically differ with Shri Uma Shankar Dikshit and I am critical of many of the things that he does. But I never thought that his own party Members did not have confidence that he could represent the party. Anyway we live to learn. And that is a good thing.

Trading in education in the regime of the Congress during the last 25 years has been a very profitable proposition and people who have been trading in education are doing quite well. At the same time they are very successful, in collaboration with the people in power, in ruining the future of thousands of young boys and girls. At the same time the standards in teaching, because of bungling, are going down day by day. You can give a degree or diploma to anybody and also thrive and not endanger yourself individually for the time being then and there. But as far as doctors and drivers are concerned, if you give something which they do not deserve you may become the victim yourself anytime.

Guru Gobinda Singh College affair is one of the worst scandals. They had one last year Mr Dikshit had a lot of features on his cap. There was the Patliputra Medical College where they had collected nearly 60 lakhs of rupees, mostly in the hands of Congress men.....,

AN HON. MEMBER: Rs. 80 lakhs.

SHRI JYOTIRMOY BOSU. My friend says Rs. 80 lakhs—collections by people in the ruling party, swallowed and digested, no digestion, no prosecution, no trouble at all.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT): This reference to Rs. 80 lakhs by the ruling party..

SHRI JYOTIRMOY BOSU: People who were connected with the ruling party.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Let him explain how they were connected.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I require some time to collect these materials. I shall make a statement within 7 days. Your chief whip in the Punjab Legislative Council is connected with that.

Coming to the history of the college, the Guru Gobind Singh Vidya Sewak Society which is registered under the Societies Registration Act 1860 sponsored a first rate medical college in Faridabad in December, 1971 and invited applications from all over India and abroad to the aforesaid medical college by advertisements. According to the salient feature of the prospectus all the necessary requirements of a medical college were offered to the prospective candidates. We must mention here that the essential criterion for admission for those who have a minimum of 45 per cent marks was the payment of Rs. 20,000 in a lump sum by each student. Out of this amount Rs. 10,000 was just donation and Rs. 10,000 was to be adjusted towards fees for full course. We want to know where is this money.

Under the notification number S.O. 62/PA 14/63/S. 272, dated the 19th April 1972 regarding approval of Guru Gobind Singh Medical College, Faridabad under section 2 of the Punjab Anatomy Act, 1963 . 449, the establishment of Guru Gobind Singh Medical College was approved. They say, "We enclose herewith a true copy of this notification. Sir, may I hand it over to you for laying a true copy of the notification on the Table? I shall authenticate it as soon as you have had a look at it.

Who are they? The Guru Gobind Singh Vidya Sewak Society which sponsors this college comprises of only brothers, sons, sisters and brothers-in-law of Mr. Gian Singh Purewal, who is the secretary of the aforesaid

[Shri Jyotirmoy Bosu]

registered society. We are giving below the names of the members of the Guru Gobind Singh Vidya Sewak Society:

1. Lakhjit Singh Purewal—Chairman.
2. Gian Singh Purewal—Secretary.
3. Jagtar Singh Purewala treasurer.
4. Piara Singh Attwal.

5. Surjit Singh Attwal—MLC. I think he is now MLA. Mr. Surjit Singh Attwal is the Chief Whip of your party in the Punjab Legislature. Therefore, let us not go much deeper into the matter. When you are trying to find it out, you might get a snake.

What is said in the prospectus? A rosy picture was given. According to Mr. Dikshit's department's requirements, for full-fledged medical college, they must have enough money of their own, building of their own, adequate apparatus and equipment. But there is not even a minimum fulfilment. The deficiencies were severe. The college has no building of its own and the classes were held in a concrete shed like building, which was previously used by a small radio-assembling industrial unit. The dissection hall which in a way forms part and parcel of the first M.B.B.S. course is situated in a small gallery on one side of the building. The physiology laboratories are too inadequate in all respects. The same tragic state prevails also in the Biochemistry Laboratory. The fact that an anatomy museum is essential in a medical colleges, we think, is still unknown to the management. For the study of social and preventive medicine, the students are to go to rural health centres and have to get practical knowledge. The college has no qualified Principal. Even the existing Principal is not allowed by the management to do anything even for the betterment of the students. The college has no Registrar. Though the

college is in Haryana, the hostels are situated very far away, 15 miles; boys hostel in Faridabad and girls hostel in Delhi. That is the position. The only way to save the career of students is that the Government should take it over. I shall come to that later on.

Coming back to that, Mr. Attwal happens to be very close friend of the present Chief Minister of Haryana, Shri Bansi Lal, against whom there are serious charges of corruption. Mr. Dikshit is fond of him, he has been protected and has been given a clean chit. That is a matter of regret. The inquiry is going on. It is highly improper, motivated and unwarranted. Therefore, this thing is moving so well in Faridabad and nothing is happening. The Government is hand in glove with the miscreants and making money and sharing the booty of each other.

I again quote:

"That the Guru Gobind Singh Vidya Sewak Society has collected Rs. 20,000 from each candidate and has thus collected about Rs. 44 lakhs in total and has the moral and legal duty and liabilities to honour their assurances given in the prospectus which are the absolute requirements for a Medical College which now they have callously and indifferently ignored in spite of our repeated demands....

Affiliation to a University is an essential requirement for any Medical College and which was guaranteed to us before the end of one year of our admission. But so far, Punjab University to which our college has to be affiliated has not given affiliation....

That the 221 students who have taken admission into this college did so in the belief that there would be no difficulty in affiliation of this college with the Punjab University and in its recognition by the

Haryana Government because important persons like S Surjit Singh Arwal, M.L.A., Punjab and S Gian Singh Puralwal, Ex-President of Gurdwara Parbandhak Committee were associated...."

They were involved and therefore the boys were taken for a ride

Mr Dikshit I regret to say did not give us correct picture I have given the document by which the Punjab Government has granted some sort of recognition to this Medical College. The Haryana Government has given some sort of recognition

Further I quote

"Subsequently it came to the notice of the State Government that the society had unilaterally decided to open a medical college at Faridabad and had issued a prospectus inviting applications by November 10 1971. The State Government issued a press note on November 5 1971 in which they declared that they had not approved of the setting up of a private medical college. Faridabad

I have given you Sir a true copy of the notification of the Punjab Government which approves, affiliates in a way and recognises this College. I want to know why is it that Mr Dikshit did not clarify it. When there is a serious situation about doctors in the country why is it that these chaps have not been prosecuted so far? It is because they have been protected by the people in power

This is one part of the story. The other part of the story is that there is a gloomy picture in the country and there is perpetual Government failure in this regard. It says

"While students clamour for seats in medical colleges and the majority of population in the country goes without doctors, there are over half a dozen medical teaching shops

which charge a capitation fee ranging from Rs. 5000 to Rs. 13000 from each student in return for unsatisfactory facilities for imparting medical education

Then another report says

It is shocking that the country simultaneously faces a shortage of doctors and a large number of unemployed doctors. According to Dr Sinha the number of unemployed doctors at present is 15000 to 20,000 and this number is expected to go up "

At the same time they say there is a huge number of unemployed doctors and there is a great shortage of doctors in certain areas. Northern India comes within that category

There is another quotation which says

Recently a large number of first division pre-medical student could not get admission to the medical colleges in Delhi because there were no seats. The Union Health Minister advised the students to abandon their medical course and instead complete their BSc course

After that what did they do? Did they hang themselves or do they loiter on the streets of Delhi to starve themselves? So I say this is one of the root causes for the student unrest and frustration—they have been maltreated and defrauded. They have been given the worst deal by this Government. They talk of linking education with productivity. But no action has been taken. Nothing has been done about it. There are no MBBS seats for 180 students. There is another clipping here about shortage of doctors. I have already said

Finally I want to appeal to Mr Dikshit not to be guided by political considerations, not to be guided by considerations of giving protection to those who are dishonest, who are bad, who are anti-social, who have cheated

[Shri Jyotirmoy Bosu]

the students. Please take drastic action against them, and it must be immediate. You take over the institution at once, inquire into it and prosecute the offenders. And, for the time being, put those boys and girls in a different Medical College. I want to clear and categorical assurance on this here and now.

Thank you, Sir. I also thank Mr. Dikshit,

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Vasant Sathe. I will draw the attention of the hon. members to the fact that only one hour is allotted. Kindly be brief.

SHRI VASANT SATHE (Akola): How much time can I take?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Five minutes.

SHRI VASANT SATHE: Please give me seven minutes, Sir.

As has been pointed out earlier in the statement of the Minister and also in the speeches made here, this is one of the serious instances where a society, formed by a family, has exploited the names of Guru Gobind Singh, Sardar Swaran Singh and Shri Gurdial Singh Dhillon, Speaker, to set up a so-called Medical College which is housed in a rented building, a shed, 60 x 200, in which the entire College including canteen, the anatomy and lecture halls—all there are partitioned by wooden partitions—is located and 200 boys are supposed to be taught.

When this fraud was brought to notice here, protection was taken under this. May I say, to begin with, that these boys have been agitating in a most peaceful, disciplined and decent manner uptill now. Normally we know whom students become restive, how the unrest erupts. But here it must to said to the credit of the boys that, although some of them were in *dharma* in front of the Minister's house, yet..

AN HON. MEMBER: Boys and girls.

SHRI VASANT SATHE: Yes. Yes, by and large, their agitation has been most peaceful, although the women students, as has been stated even in the report to the Police, were harassed and threatened by certain hired agents of the management here. That is the seriousness of the situation.

Last time when the Minister made a statement here, the Management had come out with a booklet which has been sent to all Members of Parliament—we have received it—and also to the Minister, and they have tried to deny these things. Let us take them at their own statement and see how they expose themselves completely through their own pamphlet. Now what do they say in this? They began by saying that the Minister of Health made a wrong statement. They charged the Chair also. This is what they said in para 3:

"You have observed subsequently from the Chair that you sent your message of good wishes as a matter of routine and you were subsequently shocked to learn that your message and photograph have been attached to the prospectus."

Thus you have been misled

Here is the book, Sir.

All that the students had stated in their Memorandum was:

"It also deserves to be mentioned that the prospectus of the Society for its Guru Gobind Singh Medical College, Patna, contained messages of good wishes and appreciation of work done by society by highly praised persons like Sardar Swaran Singh, Minister for External Affairs, S. Gurdial Singh Dhillon, Speaker, Lok Sabha, Shri Bansi Lal, Chief Minister of Haryana and Maharaja Patiala, Shri Yadvinder Singh."

This is what the students had stated. All these people say that, in their

Memorandum, the students had misled.

Here is the Prospectus with the photograph of Guru Govind Singh on it, and inside the very first page is the message by Sardar Gurdial Singh Dhillon, saying, 'I am very glad that the Guru Gobind Singh Vidya Sewak Society has decided to start an institution... at Faridabad...' Next is Sardar Swaran Singh's message. It is all in the prospectus. The third is from Mr. L. N. Mishra. The fourth is by Mr. Bansilal and the fifth is from the Maharaja of Patiala.

Sir, if this is not exploitation of big names, what else can it be called? An exploitation of the most cheap type, trying to exploit big and respected names of the country for a very derogatory and cheap method of expropriating money from poor students
.. (Interruptions.)

Now, Sir, kindly see this.

MR. DEPUTY SPEAKER: All that shows that you have to be very careful when you are asked to send messages

SHRI VASANT SATHE: Last time, the Speaker said that we used to send messages in good faith...

MR. DEPUTY SPEAKER: We have become wiser now.

SHRI VASANT SATHE: They have charged Rs. 20,000 from every student and they have the check to say this in this statement. Sir, last time the hon. Minister stated that it has been the declared policy of the Government which has also issued a directive to the State Governments that no capitation fee should be charged or even donation be taken. Here, what does the management say in their reply? This is what they say:

"The Minister makes a mention of the capitation fee. We have undoubtedly charged Rs. 20,000 from some of the students

SHRI JYOTIRMOY BOSU: From all of them.

SHRI VASANT SATHE: They have illegally collected Rs. 20,000—Rs. 10,000 as capitation fee and Rs. 10,000 tuition fee and other charges for the entire period of 4½ years. Then they say—you kindly see how they contradict themselves:

"We are enclosing a copy of the prospectus..."

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is all Congressmen.

SHRI VASANT SATHE: Do not detract the seriousness of the debate. Otherwise, we will not be helping the students.

SHRI K. D. MALAVIYA (Domariaganj): It is a political buffoonery in which Mr. Jyotirmoy Bosu is indulging

SHRI VASANT SATHE: They say:

"You have been supplied with wrong information by somebody."

And then they say:

"As you will see from para 2, the Minister of Health, Shri Uma Shankar Dikshit has not given the correct information."

That means that they are alleging that he said the incorrect thing when he said that the Society unilaterally decided to open a Medical College at Faridabad. This is obvious from the order of the Government of Haryana passed on 19th April 1972 and subsequently by the Deputy Commissioner, Gurgaon. Then they ask: 'How can we unilaterally start a Medical College when the purpose was not simply to start a college but to impart proper medical education to the students which can only be possible with due prior clearance....' Mind you—"With due prior clearance of the Haryana Government, the Medical Council and the Punjab University". What a cheating is it. The Punjab University till

[Shri Vasant Sathe]

this day have not given them affiliation. The Medical Council till this date has not given them sanction that is required under the Medical Council Act. Then, in the next para they say.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): What about the Haryana Government?

SHRI VASANT SATHE: They come only under the Anatomy Act. Haryana Government is nobody to give sanction for starting a Medical College. They come under the Anatomy Act and the permission they have given is for dissecting the dead bodies. That is a different thing.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Is it not inter-related?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: How can you dissect the dead body when there is no Medical College?

SHRI VASANT SATHE: In that sense, the Haryana Government is involved.

I am saying that this statement is not correct. They say in para 7.

"From the very start we established contact with the Punjab University so that the college could be affiliated to University for reasons known only to the University, the affiliation has not been given."

Then comes the most shocking thing Sir. They denied the Minister's statement. See what a bogus statement they are making.

"The students in their Memorandum have contended, a point which was subsequently supported by Mr. Pilloo Mody and the Health Minister, that the Society has appointed only a few teachers and the number is hardly adequate for teaching. They also stated that the college has no

Principal. We have 23 professors and other members of the teaching staff who are well qualified and can secure such a position in any medical college. The principal of the college is Mr. so and so.... A copy of the list of names of Professors etc. is enclosed for your kind information."

Here is that list, Sir, In this list only one person is a Professor. All the rest are lecturers or demonstrators. The total number in the list is 17. Where are the '23 professors'? Even Mr. Pilloo Mody could have been a Principal. Because, this College, to begin with, had only a B Com. who continued to be Principal and also Registrar at the same time. Now the person who is the Principal is not qualified even under the Indian Medical Council Rules or even the University rules, because he has only one year's experience in teaching. So Sir, this college has a staff which is not qualified at all. Also, it has a library, as they say. But do you know the number of books they have? They have 30 books! Yet, they say, they have a "Well-equipped library". This is what they say, although the library has only 30 books. And they charge fees for that. How can they say "The Society has also provided a very well-equipped library for reference of students"? The Minister's statement has mentioned that the Management closed down the college indefinitely from 25th October and they deny and say that this is not correct. You will therefore see from their own statement what a wrong statements they are making. The memorandum of the students is fully proved by their own statement.

Now, Sir, what is it that we are going to do about it? Are we going to say, after all, this is a State subject? I beg of you to consider this situation.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: This is a State subject, fortunately or unfortunately.

SHRI VASANT SATHE: Under the Indian Medical Council Act and Rules thereunder, the Centre is having this power.

SHRI ATAL BII ARI VAJPAYEE: Dikshitji is not a State leader.....

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: I am servant of the people and member of the party...

SHRI VASANT SATHE: This institution should be taken over with all the land, with the money it has, (Interruptions) with the money it has collected by fraud, whatever may be available now. If the State Government has to take it over, they always get grants from the Centre. Is he going to take it over and run it as proper medical college and see that it fulfils the requirements of affiliation to Punjab University? There are 200 boys. There are boys who have come from abroad. Their careers should not be ruined. This is the minimum requirement that has to be met. It is not enough saying—punish them for fraud. It is a matter of law and that can be pursued and the law will take its own course. But as far as students' future is concerned—we are mainly concerned with that—there is no use making a political capital out of this issue; these boys have had no political angle in their agitations. We from all sections support their cause. Let Government look at the issue in the larger context and see that this college is immediately taken over and run as Government Medical College. Thank you.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): You have announced only that we are going to have this discussion only up to 6 p.m. I suggest that we should extend the time. In fifteen minutes from now, how do you propose to complete the discussion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I suppose it has to be extended. It cannot be finished in 15 minutes.

श्री रामनाथार शास्त्री (पटना) :
गुरु गोबिन्द सिंह कालेज फरीदाबाद की संभावक मंडल में जो व्यक्तित्व है उनके बारे में अभी बोलने सुना है। यह संभावक मंडल नहीं है और अगर उन्हें उनमें की ज्यादात कक्षा बाने तो कोई कतिकवोमित नहीं होगी। जनता को घोषा देकर, विद्यापियों को बचाना देकर, सरकार का बरद हस्त हासिल करके फरीदाबाद में ही नहीं पटना में भी किते कलने कारनामे इस तरह के लोग कर चुके हैं, इसकी जानकारी हिन्दुस्तान के लोगों की पूरी तरह में है।

17.46 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY in the Chair]

श्री दीक्षित जी ने बीस नवम्बर को अपने बयान में कहा था कि फरीदाबाद में जो गुरु गोबिन्द सिंह मेडीकल कालेज है, उसे हरियाणा की सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है, उसे मंजूरी नहीं दी है। लेकिन इनके इस कथन के बावजूद हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री बी०एल० कडूजा ने जो कहा था, जो बयान दिया था, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है :

"In exercise of powers conferred by clause 1 of section 2 of the Punjab Anatomy Act, 1963, the Governor of Haryana hereby approves Guru Gobind Singh Medical College, Faridabad, for the purposes of the said Act."

मंत्री महोदय यहां बार-बार कहते रहे हैं कि फरीदाबाद गुरु गोबिन्द सिंह मेडीकल कालेज, पटना के गुरु गोबिन्द सिंह मेडीकल कालेज और पटना के राधेजीपुर मेडीकल कालेज या और भी किसी क्षेत्र में जो मेडीकल कालेज खोल कर रहे हैं, उनको सरकार स्वीकृति नहीं देती। लेकिन हरियाणा सरकार के अधिकारी इस तरह का बयान निकालते हैं।

भाषने अभी सुना, चाहे आहूत ने कहा है और भी बहुत से भी कहा है कि-मंत्रियों का बारीबार्द जाता है, बारीबार्द प्राप्त करके

[श्री रामावतार शास्त्री]

ये छात्रों की जमायतों विद्यार्थियों को भ्रम में डालती हैं और विद्यार्थियों को भरोसा दिलाती हैं, कि विद्यार्थियों का उनको समर्थन प्राप्त है, उनका बरप हस्त प्राप्त है। जब ऐसी बात होती है तो विद्यार्थी वर्ग-सबकने लग जाता है कि वह मैडिकल कालेज जरूर सही होगा और इसलिए वे वहां पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वहां केवल हिन्दुस्तान के छात्र-छात्राएं ही नहीं बल्कि देश के बाहर के लोक भी पढ़ रहे हैं। गुरु गोबिन्द सिंह कालेज पटना में भी पढ़ रहे हैं

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्री रामावतार शास्त्री: श्रीों को आप ने पंद्रह-पंद्रह मिनट दिये हैं

सभापति महोदय: आप सुनिये। पीछे आप ने चार घंटे ले लिये थे। इसके लिए एक ही घंटा है। इस वास्ते आप जल्दी समाप्त करें। जितना शार्ट हो सकता है करें।

श्री रामावतार शास्त्री: भ्रम में फंस कर 221 छात्र छात्राएं फरीदाबाद में पढ़ने आ गये। अब उनके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है उसे आप और हम देख ही रहे हैं। आप ने सुन ही लिया है कि पढ़ने के लिए वहां कोई सुचारु व्यवस्था नहीं है, भकान नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो सामान होता है, वह भी नहीं है। तब वहां पढ़ाई कैसी होती होगी, इसका आप अनुमान स्वयं लगा सकते हैं।

जैसा कि अभी बताया गया है, वहां पुस्तकालय में केवल बीस किताबें हैं, जब कि एक-एक छात्र से पुस्तकालय के नाम पर दो-दो सौ रुपये बसूल किये गये हैं। आप अनुदाशा लगा सकते हैं कि 221 छात्र-छात्राओं से कितना रुपया बसूल किया गया होगा। मंत्री महोदय की नीति कुछ भी क्यों ब हो, लेकिन वह इन ठगी करने वालों को

प्रोत्साहित करने वाली है। अगर मंत्री महोदय उनको प्रोत्साहित न करते, तो एम०एल०एच० उन ठगों की कमेटी के मेम्बर न होते और यह स्थिति भी पैदा न होती।

इस स्थिति में हम यह पसन्द नहीं करेंगे— और मंत्री महोदय भी पसन्द नहीं करेंगे—कि इतने छात्र-छात्राओं का जीवन बर्बाद हो। उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी ही चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री रामावतार शास्त्री: आप ने अन्य सदस्यों को पंद्रह-पंद्रह मिनट दिये हैं।

सभापति महोदय: आप ने काफी टाइम ले लिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): सभापति महोदय, आप को शुरू से ही यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि सदस्य ज्यादा टाइम न लें।

श्री रामावतार शास्त्री: अगर आप मुझे और समय नहीं देते हैं, तो मैं विरोध में नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय: नहीं, आप बोलिये।

श्री रामावतार शास्त्री: मैं चाहता हूँ कि गुरु गोबिन्द सिंह शिला सेवक सोसायटी में जो मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर हैं, सरकार उन सबके खिलाफ कार्यवाही करे। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाये, जिस तरह बिहार में पाटलिपुत्र मैडिकल कालेज के अध्यक्ष को, जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, जेल में डाला गया और अन्य लोगों को भी जेल में डाला गया।

छात्र-छात्राओं से जो कैपिटेशन की ची गई है, उस राशि को ले कर उन्हें वापिस किया जाये। हरियाणा सरकार को कहा जाये कि वह इस कालेज को अपने ह्रास में ले

ले और अगर वह समर्थ न हो, तो भारत सरकार इसको अपने हाथ में ले ले, ताकि उस कालेज के छात्र-छात्राओं का जीवन बर्बाद न होने पाय ।

जहां-जहां निजी मेडिकल कालेज खोले गये हैं, उन सबको सरकार अपने हाथ में ले ले और किसी को निजी मेडिकल कालेज खोलने की इजाजत न दी जाये । जिन लोगों ने ठगने का पेशा अपनाया है, उनको माफ करना महा-पाप होगा । उनको माफ करके मंत्री महोदय पाप के अधिकारी होंगे । वह उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे । सारे देश में ऐसी व्यवस्था की जाये, जिससे इस तरह की ठगने वालों की जमायत को रोका जा सके, जो पैसा कमरने के लिये सब जगह धूम रही है । सब मेडिकल कालेजों में पड़ाई निर्धारित स्टैण्डर्ड के मुताबिक होनी चाहिये और मेडिकल कौन्सिल की सिफारिशों को ठीक तरह से लागू किया जाये ।

अगर मंत्री महोदय इन तमाम बातों को तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे देश के नीजवानों का जीवन बर्बाद होता रहेगा । हम और वह समाजवाद का नाम लेते रहेंगे, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होगा ।

मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय आज ही ऐसी कार्यवाही की घोषणा करें, जिससे छात्र-छात्राओं को सन्तोष हो और हमें भी यह सन्तोष हो कि सरकार ने सही दिशा में सही कदम उठाया है ।

SHRI PILOO MODY (Godhra): I am thankful to you for calling me. I will not repeat what has been said. Every bit of what has been said is true except perhaps that nobody knows that out of the 17 teachers they say have been employed, 2 are non-existent, another 5 were appointed in the last 15 days or month and, therefore, the statement that has been made in this booklet as shown by Shri Sathu because of its inaccuracy can only

lead us to the conclusion that even in the defence of an organisation like this, there is a considerable amount of *golmal*.

Sir, the very fact that somebody has to go through the trouble of building up a defence like this, substantiated with a sheaf of papers in which he even gave how many kilos of a particular chemical he has in his cupboard, leads me to believe that the whole thing is a farce. I have already initiated this matter in this House a few days ago, and I want that the Minister should see it through today. I would like to hear the Minister, but unfortunately I will not be here to listen to his reply because I have to go somewhere. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

SHRI PILOO MODY: What I would like the Minister to satisfy us about today is that he will take certain positive steps to take over the institution lock, stock and barrel. I am not interested in the constitutional niceties that he will bring forward between the Central Government and the State Government. I am just not interested in excuses. I am only interested in performance.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: But they are facts.

SHRI PILOO MODY: I want the Health Minister to perform; not to give us reasons why he cannot perform. Therefore I would like to hear from him that he has either taken it over lock, stock and barrel—

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer): For once at least he is for State take-over.

SHRI PILOO MODY: But he is unfortunately a little hesitant. Secondly, I would like that a greater assessment of the institution and its existing management be made immediately. If necessary, outside managers or whatever it is should be inducted into the institute; to get a

[Shri Pilo Mody]

categorical assurance from the All India Medical Council of what are the requirements that are needed to put this college on its legs; an assurance from Punjab University that they will recognise it provided the following conditions are fulfilled, and the Government must take upon itself the responsibility of seeing, like a wet nurse if necessary, that these requirements are fulfilled by the existing management.

Because I want to take a constructive attitude, there is no point in saying: "Take it over." I am interested to see that the study of these boys is not in anyway interrupted even by a day and that they will get their degrees in time as advertised and stated. These responsibilities I charge on the Minister of Health this evening, and I hope that he will be man enough to accept them.

DR. KARNI SINGH (Bikaner): Mr. Chairman, Sir, there is absolutely no doubt that a sub-standard college has been started and unfortunately it has resulted in an absolute fraud on the student community of our country. I have had occasion to meet many students from this Faridabad college and I can only say this much, that it is a heart-rending story, and as Mr. Sathe has very correctly put it, it is a human matter and it must be dealt with as a human matter and solved as such.

These boys and girls are going to lose one year, and it should be the attempt of all of us in this House now and the hon. Minister opposite to see that the students under no circumstances lose one year, because in this highly competitive life that we are living in, one year lost means they lose a great deal of seniority in the future years in the competitive examinations.

So much has been said about the angry youth and youth in revolt. I

feel that with the dismal future that there is before India's youth, this fraud adds further insult to injury.

श्री सतपाल कपूर : राज्यों का फ्यूचर डाक है, यूव थोर स्टूडेंट्स का नहीं ।

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

DR. KARNI SINGH: It is a dark future. I repeat I feel that there is a dismal future before the students for the reason that there are not enough jobs or openings for the number of boys coming out from the colleges. I am trying to finish my speech in three minutes. I feel that the hon. Minister cannot stand purely on legal niceties. A situation has been created and I feel either that this particular college can be given temporary affiliation to the Delhi or the Punjab University; or, alternatively, these students can be absorbed by the medical colleges of Punjab, Delhi and Rajasthan until such time as this college is put on its feet. We are far more concerned at this stage to see that those students under no circumstances lose one year, and if they lose one year they are going to put them at a disadvantage with other students in the country.

18.00 hrs.

SHRI A. P. SHARMA (Buxar): This is another disgraceful incident in the country that has taken place in our educational institutions, the first being in the same name, in the Magadh Medical College in Bihar, Patna. From the statement it is quite clear that about 221 boys and girls not only from our country but from some foreign countries also have come to this college by paying a capitation fee of Rs. 20,000. It is no fault of these boys and girls that they have been invited to join and take admission in this Medical College. We also find that there has been a Gazette Notification of the Haryana Government to this effect. Therefore I suggest, as other hon. Members

have said, that alternative arrangements should be made for continuing the education of these boys and girls. Whether it is a States subject or Central subject, an enquiry should be instituted into the whole affair of this college and the people who have behaved in this manner should be punished.

MR. CHAIRMAN: The hon Minister.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I have been one among those who have demanded this discussion. I have given my name in time and I have been in correspondence right from the beginning and I want to know whether I shall have an opportunity to say something on this matter.

MR. CHAIRMAN: It is not necessary that on every subject the representatives of all parties should speak.

श्री सतपाल कपूर : प्रोबलम इसमें केवल इतनी है, श्री बन्धु ने जितने इसमें इलजाम लगाये हैं, वे सब बने बुनियाद ही धीरे चलत है। जहाँ तक सम्बन्ध इस बात का है कि इस मनेजमेंट ने स्टूडेंट्स के साथ फ़ाड किया है, या नहीं किया है, चीरिंग की है या नहीं की है, मैं बिल्कुल श्री बन्धु, से, साठे से, श्री पीलू मोदी से धीरे डा० पांडेय से इतिफाक करता हूँ कि इस मनेजमेंट ने एक प्रकार का कौमो-पलाज क्रिएट करके धर्म के नाम पर धीरे सीडरों के नाम पर उनके असेज प्रगवा कर स्टूडेंट्स का एकस्लायट किया है। अब सवाल यह है कि इस मामले में किया क्या जाये। सरकार क्वैरी है कि हज टैक धीवर करने के लिये तैयार नहीं क्योंकि दो करोड़ रुपये खर्च इसके ऊपर आता है। मैं तजवीज यह देना चाहता हूँ कि इस मामले को पोलिटिकल इश्यू बनाई तो इससे स्टूडेंट्स का मसला हल नहीं हो सकता। या इसको सेंटर धीरे स्टोड की आबजक बनाये धीरे कहें कि यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सेंटर बजट नहीं दे सकता, मैडिकल काउन्सिल को अपनी कमीशन रिपोर्ट करने को तैयार

नहीं है तो इससे समस्या हल नहीं होखी। स्टूडेंट्स की जिन्दगी इस तरह से ज़ाया जाए वे इस तरह से सफर करते हैं धीरे चीरिंग के शिकार हों जो मनेजमेंट फर चुका है यह ठीक नहीं है। यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि यह उन लोगों पर मुकदमें चलाये धीरे उनसे रपया बसूल करे। लेकिन धरर गवर्नमेंट मनेजमेंट को धरवर भी कर वे तो भी मैडिकल कालेज के स्टूडेंट्स की जिन्दगी का क्या होगा? मेरी तजवीज है कि फीरी लीर पर गवर्नमेंट इस कालेज की टैक धीवर करले। यह ठीक है कि इसमें बहुत बड़ा एमाउन्ट इन्वाल्ड है। लेकिन फरीदाबाद में पांच सौ डॉल्स का एक अस्पताल सरकार खोलने जा रही है। उसको इससे अर्टैच करना चाहिये। इसमें एक करोड़ रुपये खर्चक बच जाते हैं जो आलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने फरीदाबाद में हास्पिटल खोलने के लिये धरवे बजट में एलाट किये हुये हैं। दूसरी तजवीज है— बाकी एक करोड़ रुपये सरकार के पास कहां से आये? मुझे पूरा यकीन है कि यह मनेजमेंट जिन्होंने कहा है कि हमने 27 लाख रुपये इकट्ठा कर लिया यह 27 लाख रपया भी वे नहीं देंगे। यह चीट है, फ़ाड है। इसके लिये मैं तजवीज यह पेश करना चाहता हूँ कि धरर सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉसिबिलिटी ले धीरे हरयाना गवर्नमेंट इसमें कुछ पैसा दे तो गुरु गोविन्द सिंह के नाम पर ऐसे लोग भी इस देश में हैं, मैं कहता हूँ कि धरर गवर्नमेंट यह रेस्पॉसिबिलिटी ले तो 25 लाख रुपये मैं इकट्ठा करके गवर्नमेंट की दूंगा, गवर्नमेंट इस कालेज को टैक धीवर करे। इसलिये मैंने यह कहा था कि इस मामले पर गुरु गोविन्द सिंह का नाम बदनाम किया जाय, लीडर का नाम बदनाम किया जाय धीरे बंशी लाल को क्वीन चिट दे दी या नहीं दे भी इससे इसका कोई तालुक नहीं है। हर मामले में पोलिटिकल ले आए इससे कुछ होने बाजा नहीं है। मेरा कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टैक धीवर करे तो 25 लाख रुपये पेशाव

[श्री सतपाल कपूर]

के लोगों से इकट्ठा करके मैं लाने के लिये तैयार हूँ। मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।

PROF. MADHU DANDAVATE:
Sir, there are occasions when the debate must not be converted into a debate between the ruling party and the opposition. This is an occasion on which members belonging to both sections of the House must think of some constructive way to rehabilitate the 221 students back in their educational institution. Unfortunately, in the statement made by the Health Minister last time, he took a certain position which may be correct from a legalistic and technical angle. But life is something more legalism and technicalism. For instance, he did indicate on the floor of the House that Haryana State Government had issued a press note on November 5, 1971 saying that they have not approved the setting up of a private medical college at Faridabad. It may be technically correct, but it completely conflicts with what was stated by Mr. B. L. Ahuja, Secretary of the Medical and Health Department of Haryana Government on 19th April 1972 which was published in a Gazette Extraordinary, namely,

"In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 2 of the Punjab Anatomy Act, 1936, the Governor of Haryana hereby approved Guru Gobind Singh Medical College, Faridabad 6" etc.

This particular statement was seen by the teachers and students. I am personally involved because many of my students in Bombay University are today students of this medical college. I have therefore a personal stake in it. These students told me that after this statement, they were convinced that there would be protection given by the au-

thorities and that is why they continued to be students in that college. Therefore, I appeal to the House that priority should be given to rehabilitating the students. I do not want to make reference to the fact that some prominent personalities were involved and their messages were read by the students.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

PROF. MADHU DANDAVATE:
Yes, Sir. The difficulty is technical. Again and again the minister says education is a State subject and this institution cannot be managed by the Central Government. I suggest a *via media*. Fortunately we have the UGC which gives grants from time to time for the operational work of various institutions. This can be considered as a critical situation and if the Central Government and the Health Ministry at the Centre use their good offices, the UGC can be contacted and adequate grants can be given and this institution can be built up.

What is the *modus operandi* of the building of the institution can be left to the UGC, can be left to the Central Government and can also be left to the State Government. I make this concrete and constructive proposal which can be explored. The UGC authorities can be contacted. They have also acted in certain situations in an identical manner. I am sure, the Health Minister will not take shelter behind the technicality that this is a State subject.

On behalf of the students and the teachers involved, I would again appeal to them that they should not take a legalistic and a technical view but to see that all the 221 students are completely rehabilitated.

Lastly, the management has come out with a Memorandum which has been circulated to all the Members

of Parliament. To say the least—I am not accustomed to use such a phraseology—after carefully going through the management's Memorandum which has been circulated amongst the Members of Parliament, all that I can say is that the Memorandum is the greatest fraud that has been perpetrated and that should be thrown away into the waste paper basket.

I would once again appeal to them to see that all the 211 students are completely rehabilitated.

SHRI R D BHANDARE (Bombay Central) Mr Chairman, Sir, I am not going to make a speech. I would like to bring two facts to the notice of the House. Ever since the students have been duped the students are wandering from place to place from the MP's houses, from their own houses and therefore they are passing through a mental agony. How to remove that mental agony is a question to be answered by the hon Minister.

Then the mental agony through which the hon Minister is going is that some of the students are having a *dharna* in front of his house. When we pass by that road it is really a sight not to be seenable—I do not say an ugly sight—the student having a *dharna* in front of the house of the hon Minister. So, I would appeal to the hon Minister to remove his own mental agony also by coming to the rescue of students.

Having dealt with this point, the question is: What should be done with the fate of the students who have been duped? This is a question to be answered by the hon Minister, by the Central Government from a parents' position. As a number of hon Members have suggested and pleaded with the hon Minister, it should not be a legalistic or a constitutional view which ought to be taken. Both the Central Government and the State Government must come to the rescue

of the students. Various ways have been suggested by the hon Members who have preceded me. I need not repeat them.

Another question is: What should be done with the management? I think, it should be charged for committing a fraud on the students. The students have been duped. Prosecution must be launched against the management. These are the points that I have made. Thank you.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) Mr Chairman, Sir, I have carefully listened to the observations made by the hon. Members. So far as the feeling over the irresponsible action of the board of management of the Guru Gobind Singh Medical College is concerned and the unfortunate, distressing, situation in which the students have been placed, in both these respects I feel myself entirely one with all the Members in the House.

I was very pained to find that Mr Jyotirmoy Bosu was very eager to convert this question into a political issue. It is not a political issue. Both the first speaker and the second speaker brought in Haryana Government. Mr Jyotirmoy Bosu referred to what I said about the Chief Minister of Haryana. It is very unfortunate and it also makes one feel that when important matters of social significance are brought before the House, the responsible, the leading, Members of the House should try to present them as political issues. It has nothing to do with politics at all. (*Interruption*) I do not quarrel with his statement. This is precisely what he said. This completely conforms my impression and the point I was making.

Now let us look at this in a correct perspective. I agree with the members who have said that we must not take a purely technical or legalistic view of this situation. I entirely agree

[Shri Uma Shankar Dikshit]

with them in this. But the question is what kind of view are we going to take. Are we going to take an irresponsible, general and sympathetic attitude saying 'We are all with you', 'We have sympathies for you', 'We wish you well', 'We wish the best of luck to you', etc.? We have to find funds. The Committee that was appointed for meeting the requirements of admission of about 130 students, the first divisioners, with over 60 per cent marks and some of them with even much higher percentage, suggestions that it would require Rs 4½ crores for both non-recurring and recurring expenses. My friend, Mr. Kapoor, has assured us that he is willing to raise donations amounting to Rs. 25 lakhs. It is good, if a trust can be registered or constituted and if charitable and public-spirited gentlemen interested in education of students in Punjab and Haryana and perhaps also in Delhi—because the Head Office of that Society is in Delhi—combine together, then sufficient, initial funds can be raised, in my opinion, and then perhaps some way can be found. Let us see the picture and the issue in a correct perspective.

So far as Haryana Government and Mr. Bansilal are concerned, I have nothing to do with that. This matter, as I have said, has no political overtone at all. He said that I gave a clean chit to Mr. Bansilal. I am glad that he has given me the opportunity to make the position clear. Newspaper men came to me late in the evening after the function there had concluded and said, 'There are speculations here to the effect that the Chief Minister of Haryana is being dismissed. What have you got to say about it?' I said, 'These are speculations'. They said, 'No' and went on probing. Finally I said that 'the president of the Congress has made a forthright statement which has been published in the Delhi newspaper this morning; that should be enough because that puts

the position straight. So far as any decision about dismissal, etc., was concerned, I said, the matter had not even been discussed. This is what I said. I do not know how such a statement can be regarded as giving a chit to anybody. I do not think that he needs it, and even if he needs it, is none of my business to go about doing that sort of thing. (Interruption) That is why I said that his was very unfortunate. Then I also get the feeling that it is not merely on humanitarian grounds or for honest students that this matter has been raised, but it has been raised by those who taken initiative with a political motive with a politically motivated. (Interruption) That is what I am trying to express, I hope that such matters will be understood and approached correctly in future. I do not think that this will have much effect on my hon. friend, Mr. Jyotirmoy Bosu.

So far as the Society is concerned, as far as we have obtained the information after I made the statement of 30th November, the position is like this. I have received a copy of the reply which the University in Punjab has to this institution, to this Society. They have definitely said that one year before the starting of a college like this applications should have been made to the University, and 'as you have not done so, there is no question of our granting affiliation'. Similarly, the Medical Council also has said something to the same effect. It is true that the Haryana Government which under the Anatomy Act is required to give its permission, did issue a notification. There is no doubt about it. But subsequently, after the matter was raised in the Parliament, they have withdrawn that notification also.

So far as these people are concerned, I called the Chairman and he has not turned up. I called the Secretary. He also has not turned up. They sent one Office Superintendent. This man has given three names of a single family and he told our officers that they are sole and exclusive members of the

Management Board. These three people are there. There is a society also. Part of the funds have been kept in the name of the society and part of the funds is in the name of the college for reasons best known to them which are very difficult to appreciate.

Then he says that there are other people whose names they have not given. The students, in their memorandum, have mentioned two or three other names also and they also said that they are members of the society.

What are we to do about it? It has to be understood that except for the Post-graduate teaching the Government of India cannot use their funds except to the extent that it is permissible under the law and where the question of provision for maintenance or raising of the academic standards are concerned, there, the Government of India does come in. But the Government of India is not in a position to pass any regulatory legislation. I consulted the Law Ministry and the Law Ministry has advised me that under the Constitution, it will be difficult for us to issue either an ordinance or being a Bill straightaway taking over the matter or punishing the people.

So far as inquiry into the case is concerned, as I said last time, that is, on the 30th November, the Chief Minister he said, and their Government has subsequently informed me in writing, that they have appointed a high-level officer to inquire into the case. Now, in this matter, the advice of the Law Ministry is that if the facts are as they appear in the memorandum of the students and as they have come from the University and the Haryana Government and if these facts are correct more or less, then, this would be a cognizable offence. We do not know whether it is so or not. But if it is so, it will be possible for the Government of Haryana to start proceedings, prosecution proceedings *suo motu*. But I will go into the matter further and if this opinion is confirmed, we will take up the matter immediately this evening or sometime tomorrow

with the Haryana Government so that legal proceedings can be started, if they are permissible under the law.

As I said on the 30th of November, I received their memorandum on the 15th and on the 16th I wrote to them after taking a legal view of the matter suggesting that they should file the First Information or a complaint in Faridabad or some suitable place as advised by lawyers so that the Haryana Government can start proceedings immediately. But, to this day, none of the students has taken any such step. Therefore, I asked the Law Ministry whether without the students going and lodging such a complaint, the State Government is in a position to take such a measure and they have said that, subject to the case being as it has been stated, it should be possible for them to do so. After ascertaining the facts, I shall immediately take up the matter with the Government of Haryana so that action can be taken... (*Interruptions*)... regard to the UGC business raised by the hon. Member, this is the position.

This question can arise only after the Punjab University is satisfied. Only if the Punjab University is fully satisfied that the minimum requirement under the University Act for affiliation is met can this be done. So far they have not been satisfied. Several hon. Members have pointed this out. There is hardly even the minimum of minimum, there is hardly anything at all. There is one large godown which is converted into a college. They may call it by all manner of names which are not really substantial or tenable. Then, about professors and teachers, the information given by hon. Members is quite correct. The situation must be worse, it cannot be better than what has been stated here. I am sure about it.

When some of our people went round, the place was locked. There was nobody around. The Secretary lives here somewhere in the city; he does not even come to give the information to us. He even avoids writing detailed particulars in reply to questions asked; this is the position.

[Shri Uma Shankar Dikshit]

So far as funds are concerned, they say funds had been charged from 161 students..

AN HON MEMBER: 180 students..

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Although they had 180 students, they have got money from a reduced number. About 20 students have been admitted by them without charging them anything. The money collected is also not standard. The rate varies as Rs. 10,000 15,000, Rs. 12,000, Rs. 5,000 etc. etc.

According to the Audited Accounts that they have produced before us, peculiarly-enough, it is signed only by the Secretary, Mr. Gian Singh, the Accountant, Mr. Inderjit Singh and Mr. Hingorani, Chartered Accountant. According to this statement, the amount now left with them is Rs. 14 45 lakhs Rs. 94 lakhs are in banks and 5 lakhs money is deposited with a private limited company. It is not possible to say whether that money will be realisable or not. They give other particulars where they say: Prospectus fees Rs. 70,17,955; registration fees, Rs. 14,900; fees and other charges, Rs. 4,44,900 and donations Rs. 4,49,000 etc etc. From 89 students they charged Rs. 20,000 each, from 22, Rs. 15,000, from 1, Rs. 18,000; from 2, Rs. 18,500; from 1, Rs. 14,500; from 1, Rs. 18,000 from 6, Rs. 12,000, from 29, Rs. 10,000; again from 1, Rs. 13,000; from 2 Rs. 8,000; from 6 Rs. 5,000 and from 1, Rs. 2,500, each. There is hardly any rule or norm or standard either in the matter of admission or in the matter of capitation or advance fees collected. Suppose they had done that, the position would not have so bad, although it was undesirable in all respects. But even that has not been done.

So far as action is concerned, we shall pursue this matter with all seriousness and vigour.

So far as dealing with the students is concerned, let us understand that this seems to be something in the nature of a fraud. Fraud is going on

in the country; there are cheats in the country; there are pickpockets; there are thieves. Now, if we are going to take over the financial and managerial and other responsibilities from people who defraud other persons, there will be no end to this matter. Let us understand this. There are a large number of boys who want to enter the medical career. Earlier, the craze was for the engineering career, but now it has shifted to the medical career, for obvious reasons. I can fully understand this and sympathise with this. But, of course, it is not possible to admit every boy who passes PMT or Inter (Science). Last year, as I had pointed out, 130 students with first division could not be selected, because we could not find Rs. 4½ crores straightway. These people have taken Rs. 20,000 or Rs. 10,000. It was calculated a couple of years ago that the amount spent on one boy per year was not less than Rs. 80,000. If they had committed this wrong but had collected the full amount, they would have been able to run the college, but they have taken only one-fourth of the amount from eighty students.

Now, it has been suggested to us that we should help this college to come up and so on. I am willing; if a charitable trust is constituted, I can contact the Punjab Government, because the Punjab University is there, and quite a large number of the boys are from Punjab, and there may be some from Haryana and there may be some from elsewhere. If some such trust is willing to come forward, we can help, and I shall lend my good offices informally and even formally, necessary, with the two Governments in order to see if something like that can be done. But I have already given you an instance of a case relating to a Union territory where we have direct responsibility. The Planning Commission said that there would be ten medical colleges during this period. All these ten have been established. One was offered to the Haryana Government

two years ago, and they said that they had not got the funds, and their priorities were different, and they would not be in a position to start the medical college. Out of the ten colleges, one is in NEFA and another is elsewhere and so on. Under the plan, it is not possible to find Rs. 4 crores straightway. When we sent 50 boys to the medical college at Meerut, we paid to the UP Government about Rs. 80 lakhs. If we are going to ask any State Government to take over the students, they will calculate at the rate of Rs. 80,000 per student and ask us to shell out the money. If it is the opinion that all the functions or all the main functions, that is, health and education, the main social welfare functions of the State Governments are to be taken over by the Central Government, the method would be different. I would advise that the matter should be given more careful consideration. Immediately, it is not possible for me on behalf of the Government of India, to undertake either to take over this college or to run it.

SHRI VASANT SATHE: May I suggest that....

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Whatever suggestions hon. Members may have, I would invite them to come and give me all their constructive suggestions, and I shall consider them with all sympathy....

SHRI VASANT SATHE: Under the Societies Act, the management can be taken over....

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: No, the Union Government is not in a position to take over an undergraduate medical college. It is only post-graduate colleges that can be taken over by the Union Government.

SHRI VASANT SATHE: Under the Societies Act, the State Government authorities can take over the management.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Of course, they can take over....

SHRI VASANT SATHE: It can be taken over....

MR. CHAIRMAN: If I allow the hon. Member, how can I not allow the Members on the other side? Let him not interrupt the hon. Minister.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: This is not the only instance. This is the worst instance of this kind. We treat it as a warning. I would say once again that it is a final warning. We have already taken up the matter with all the State Governments, and I have said in answer to a question either in this House or in the other House that we have already asked all the State Governments immediately to stop admission or permission or approval to any such college in future.

श्री रामाबतार शास्त्री : बिहार गवर्नमेंट ने निजी मेडिकल कालेजों को पांच वर्षों तक कंपिट्रेशन फीम वसूल करने की अनुमति दे दी है ।

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Particularly, where there is no capitation fee or no advance, they may permit, but there also, unless and until prior permission is given, they will not be allowed. As the hon. Member has said, the Bihar Government has started it. In Bihar, there are four other colleges. There are colleges in Maharashtra, Mysore and Madhya Pradesh also, and some of these colleges are running well. It is no use saying that we should stop it from the beginning. Somebody said 'Why do you not stop it?' Is it implied that Government should keep some sort of spying system to find out who is starting and who is not starting? No, but we not be frivolous about it. It was not possible for us to stop it in advance.

[Shri Uma Shankar Dikshit]

Let me make this statement in all seriousness. As soon as the Government of India came to know about this, we took every possible, legitimate, reasonable and proper action in the matter. If a trust can now come about, if at least enough funds are there to ensure observance of minimum standards—it should be more than minimum standards—we

will try to help informally with the State Government. If such a college comes, I will take up the matter here also with the sister governments. This is all I can say.

18 36 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 20, 1972/Agrahayana 29, 1894(Saka).